PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : NAI DUNIYA

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

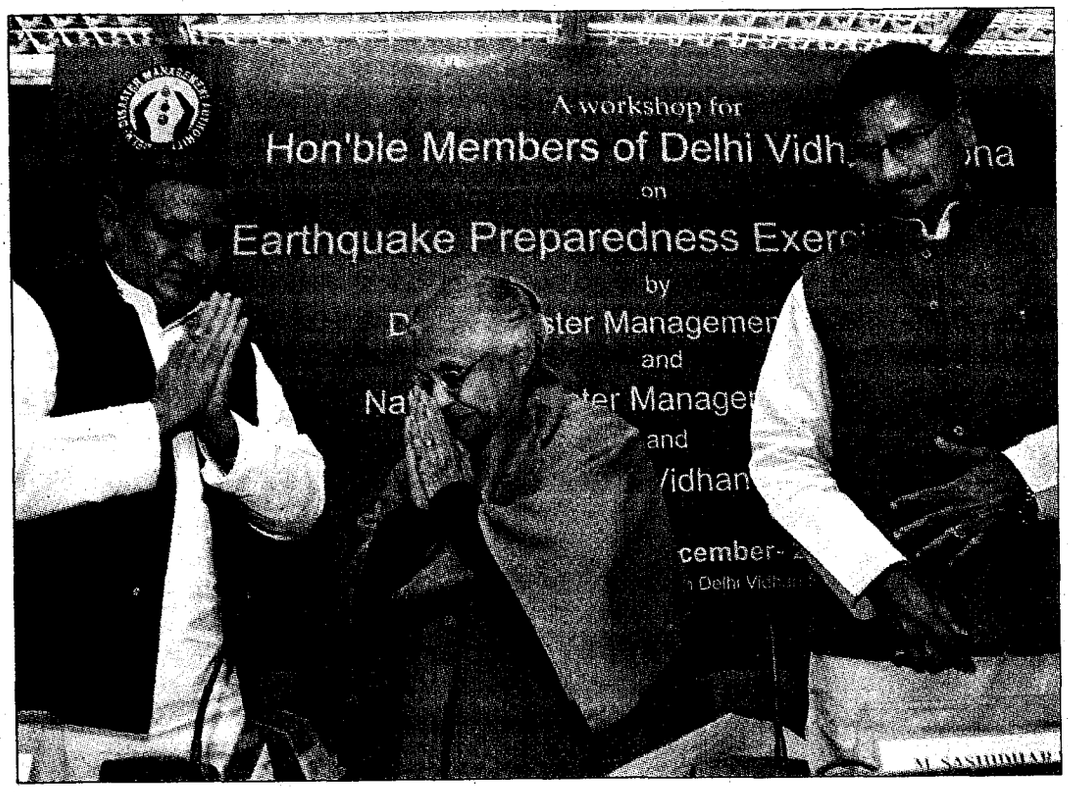

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विधानसभा में एक कार्यशाला का आयोजन किया और इस अवसर पर आपदा प्रबंधन संबंधी मूक अभ्यास भी किया (बाएं) और कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री और एनडीएमए के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी। फोटो : हरीश कुमार

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : NAI DUNIYA

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

'आपदा से निपटने को तैयार रखेंगे दिल्ली को'

नई दिल्ली (सं)। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि सरकार राजधानी को पूरी तरह आपदा से निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। आपदा आने पर जान-माल के अलावा रोजगार को भारी क्षति पहुंचता है। श्रीमती दीक्षित ने विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला में आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी, और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया।

श्रीमती दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहत है। क्योंकि ये जोन-4 में आती है। उन्होंने आपदा प्रबंधन पर जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक बनाने पर जोर दिया। आम लोगों को यह बताना चाहिए दशहत फैलाने से नुकसान और भी अधिक होता है।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : HARI BHOOMI

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

आपदा से निपटने के लिए कृतसंकल्प है सरकार

हरिभूमि न्यूज, नई दिल्ली

मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं।

प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। श्रीमती दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजय देव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से अभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि-दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पौंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जान-माल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है।

- विधायकों के लिए भूकम्प की त्रासदी से निपटने की तैयारी की कार्यशाला आयोजित
- तुरंत रिस्पौंस प्रणाली मजबूत किए जाने की जरूरत

हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जान बचाना शामिल है।

पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पौंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूर्ण सहयोग देगी।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : JANSTTA

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी: दीक्षित

जनसत्ता संवाददाता

नई दिल्ली, 22 दिसंबर। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृत संकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है। इससे जीवन, रोजगार और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है बल्कि पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन की अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डा. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डा. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व व दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति पैदा करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी है। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पोंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी संबद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डा. योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी व दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डा. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पोंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एंबुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे आपदा के समय जल्द से जल्द मदद और बचाव कार्य किया जा सकेगा। ऐसे कार्य में एक-एक पल कीमती होता है और हड़बड़ में किए गए बचाव कार्य से कई बार ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भूकम्प से सुरक्षा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 15 फरवरी, 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होगी। मुख्य सचिव त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी। सरकार आपदा प्रबंधन के उपायों पर पूरा जोर दे रही है। कई भवनों की रिटरो फिटिंग की जा रही है।

राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रेड्डी ने अपना प्रमुख भाषण देते हुए कहा कि 2004 में सुनामी आने के बाद इस प्राधिकरण का गठन किया गया। दिल्ली में जनसंख्या घनत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां आपदा प्रबंधन के कई पहलू अलग हैं इसलिए दिल्ली अन्य राज्यों से इस मामले में कुछ अलग है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में विश्वस्तरीय तैयारी की जाए। असुरक्षित भवनों का जिक्र करते हुए कहा कि महज पांच फीसद अतिरिक्त लागत से भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उनके प्राधिकरण ने शहरों में बाढ़ की स्थिति के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसका रिस्पोंस फोर्स काम कर रहा है जिसमें 12 बटालियन हैं। दिल्ली की जरूरतें पूरी करने के लिए एक बटालियन नोएडा में तैनात की गई है। एनडीएमए अपने प्रयास जारी रखेगी कि आपदा में नुकसान कम से कम हो। इस दिशा में एनडीएमए दिल्ली सरकार को पूरा सहयोग देगी।

SPAN CO
n@gmail.com

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : AJ SAMAJ

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

आपदा से प्रभावित होती है प्रगति

आपदा से निपटने को दिल्ली तैयार : दीक्षित

तुरंत रिस्पोंस प्रणाली मजबूत किए जाने की जरूरत

- विधायकों के लिए भूकंप की त्रासदी से निपटने की तैयारी की कार्यशाला विधानसभा में संपन्न
- विधायकों से आपदा प्रबंधन और एहतियात का संदेश फैलाने का आग्रह

□ मुख्य संवाददाता

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है।

दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकंप की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों का इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी संबद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलेक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है, लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पोंस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलेंस और क्लीनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे आपदा के समय जल्द से जल्द मदद और बचाव कार्य किया जा सकेगा। ऐसे कार्य में एक-एक पल कीमती होता है और हड़बड़ में किए गए बचाव कार्य से कई बार ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भूकंप से सुरक्षा पर ज़ोर दिए जाने की जरूरत है। भूकंप की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरूकता लाई जाएगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में विश्वस्तरीय तैयारी की जाए। असुरक्षित भवनों का उल्लेख करते हुए कहा कि महज पांच प्रतिशत अतिरिक्त लागत से भवनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उनके प्राधिकरण ने शहरों में बाढ़ की स्थिति के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : SHAH TIMES

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

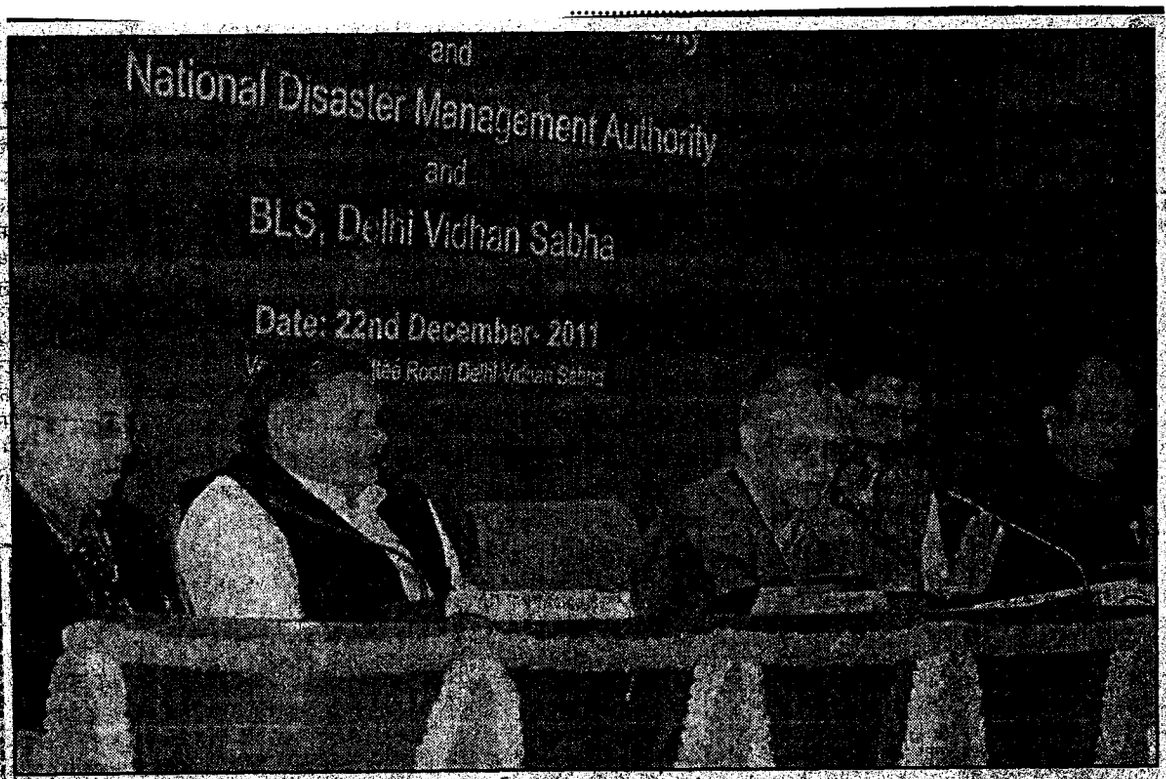

दिल्ली सचिवालय में आपदा प्रबंधन पर आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करतीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित।

हर आपदा से निपटने को तैयार: शीला

समीक्षा

- विधायकों के लिए भूकम्प की त्रासदी से निपटने की तैयारी की कार्यशाला विधानसभा में सम्पन्न
- तुरन्त रिस्पॉस प्रणाली मजबूत किए जाने की जरूरत

शाह टाइम्स संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने आज कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देष और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं।

दीक्षित ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पॉस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान [illegible] भावना को आधार विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों को इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रोनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और [illegible] की जान बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के प्रमाण मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पॉस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : LOKSATYA

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

लोकसत्य नई दिल्ली, शुक्रवार, 23 दिसंबर, 2011

विधायकों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर

आपदा से निपटना अहम : शीला

नई दिल्ली, लोसं। दिल्ली के विधायक भी आपदा प्रबंधन के गुर सीखे। बृहस्पतिवार को दिल्ली विधानसभा ने इनके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कहा कि दिल्ली की उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्पित है। जब आपदा आती है तो विनाश होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जन-जीवन अस्त-व्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डा. योगानंद शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डा. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव विजयदेव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती है। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी है। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पोंस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन अब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों को इन मुद्दों पर जागरुक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण में एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी सम्बद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है, उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डा. योगानंद शास्त्री ने कहा आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : VEER ARJUN

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

आपदा प्रबंधन के लिए विधायकों की लगी क्लास

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। राजधानी का भूकम्प जोन 4 में होने के नाते हमेशा यह आपदा का खतरा बना रहता है और तेजी से बढ़ी अनाधिकृत कॉलोनियों ने [illegible] की नींद उड़ा रखी है। यही कारण है कि अब सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए गुरुवार को दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला आयोजित की गई।

दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरी तरह आपदा प्रबंधन और इससे निपटने के लिए तैयार रखने को कृतसंकल्प है। जब आपदा आती है तो विनाश लीला होती है जिससे जीवन, रोजगार और सम्पत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है। इससे न केवल जनजीवन अस्तव्यस्त होता है अपितु पूरी मेहनत से हासिल किए गए विकास के फायदे भी ध्वस्त हो जाते हैं। प्रगति के मामले में देश और शहर कई दशक पिछड़ जाते हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में विधायकों के लिए आपदा प्रबंधन आयोजित अब तक की पहली कार्यशाला में ये विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री शशिधर रेड्डी, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानन्द शास्त्री, दिल्ली के राजस्व मंत्री डॉ. अशोक कुमार वालिया, मुख्य सचिव श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी और राजस्व तथा दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव श्री विजय देव ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

दिल्ली विधानसभा में आपदा प्रवन्धन पर विधायकों की कार्यशाला को सम्वोधित करतीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित उनके साथ हैं विधानसभा अध्यक्ष डा. योगानन्द शास्त्री, स्वास्थ्यमंत्री डा. अशोक वालिया।

कई मंत्रियों समेत बड़ी संख्या में विधायक कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित अभ्यास भी प्रदर्शित किया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्रीमती दीक्षित ने कहा कि अलग-अलग किस्म की आपदा से सभी लोगों को खतरा बना रहता है। दिल्ली में आपदा की आशंका बनी रहती है क्योंकि बम विस्फोट, आतंकवादी घटनाएं, अग्नि दुर्घटना, इमारतें ढहने और सड़क दुर्घटनाएं आपदा की स्थिति उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा भूकम्प की दृष्टि से भी दिल्ली पर खतरा मंडराता है क्योंकि ये जोन-4 में आती हैं। इसके घने बसे इलाकों में असुरक्षित इमारतें हैं जो बिना नक्शे के बनी हैं। इस वजह से भी खतरा बढ़ता है। पहले रिस्पांस का मतलब राहत, बचाव और पुनर्निर्माण समझा जाता था लेकिन इब इसके दायरे में आपदा न होने देने के लिए एहतियात और जानलमाल के नुकसान को कम से कम करना शामिल है। हमें आपदा के दौरान सुरक्षा की भावना का आभास विकसित करना होगा। इस दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधि अहम भूमिका निभा सकते हैं और लोगों को इन मुद्दों पर जागरूक कर सकते हैं। आम आदमियों को यह भी बताया जाना चाहिए कि दहशत फैलाने से नुकसान अधिक होता है। प्रशिक्षण पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एहतियात सुनिश्चित करने और नुकसान कम करने को उजागर किया जाना चाहिए और इसके लिए बच्चों, इंजीनियरों, वास्तुकारों और अन्य सभी संबद्ध पक्षों को जानकारी दी जानी जरूरी है।

PRESS REPORTS

Client : DDMA And NDMA

News Paper : VEER ARJUN

Edition : NEW DELHI

Date : 23.12.2011

उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि आपदा में सुरक्षा और बचाव पर जोर देने के लिए इलैक्ट्रॉनिक मीडिया और एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. योगानन्द शास्त्री ने कहा कि आपदा की समयावधि कम रही है लेकिन इसकी मार सदियों तक सही जाती है। आपदा प्रबंधन में एहतियात और इसके अलावा अपनी तथा दूसरों की जानें बचाना शामिल है। पुराने समय से आपदाओं के वर्णन मिलते हैं। प्राकृतिक आपदा हमेशा विनाशकारी और भयावह होती है। राजस्व मंत्री डॉ. वालिया ने कहा कि आपात स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली चालू करके रिस्पांस सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए अस्पतालों, एम्बुलैंस और क्लिनिक को उन्नत बनाया जाना और वहां के कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है। इससे आपदा के समय जल्द से जल्द मदद और बचाव कार्य किया जा सकेगा। ऐसे कार्य में एक-एक पल कीमती होता है और हड़बड़ में किए गए बचाव कार्य से कई बार ज्यादा नुकसान भी हुआ है। सभी अस्पतालों के बीच तालमेल को भी प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भूकम्प से सुरक्षा पर जोर दिए जाने की जरूरत है। भूकम्प की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली में ढाई महीने का अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें लोगों में जागरुकता लाई जाएगी। एक मीडिया अभियान भी जल्द शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 15 फरवरी 2012 को बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल होंगी। मुख्य सचिव श्री त्रिपाठी ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और आम आदमियों को आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण देने के लिए पूरा सहयोग देगी। सरकार आपदा प्रबंधन के उपायों पर पूरा जोर दे रही है। कई भवनों की रिटरो फिटिंग की जा रही है।